INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 6.865 (SJIF 2023)

भारत में शिक्षा एवं रोज़गार की स्थिति : एक अध्ययन
(Status of Education and Employment in India: A Study)

डॉ. राजेश कुमार
सहायक आचार्य
गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी,
मोहन नगर, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश।
E-mail: rajeshrajora2017@gmail.com

डॉ. दीपशिखा शर्मा
प्राचार्या
गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी,
मोहन नगर, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश।
E-mail: deepshikhas232@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/05.2023-83192576/IRJHIS2305008

शोध सारांश :

भारत एक विकासशील देश है, जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। हालांकि, भारत में शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति अभी भी असंतुलित है और इन दोनों ही क्षेत्रों में कई चुनौतियां भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी, विभिन्न राज्यों में शिक्षा असुलभता, स्कूलों की भूमिका खंडित होना और छात्रों के अस्तित्व को लेकर असुरक्षितता। इसके अलावा, भारत में स्कूलों में विशेष वर्गों के छात्रों के लिए विशेष शिक्षा के विकल्प भी कम होते हैं। विभिन्न राज्यों में शिक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों की कमी भी एक और मुख्य समस्या है। शैक्षिक संस्थानों में अधिकतर छात्रों की संख्या गणना में होती है, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षा विस्तार करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। इससे छात्र उच्च शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं और उन्हें रोजगार की संभावनाएं कम उपलब्ध होती हैं। भारत में रोजगार की स्थिति भी असंतुलित है। भारत में बड़े शहरों में उच्च शिक्षित लोगों को अधिकतर रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प बहुत ही कम होते हैं। युवाओं को रोजगार के लिए उचित उपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे उच्च शिक्षा की ओर अधिक आकर्षित हों और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।

मुख्य शब्द : *शिक्षा एवं रोजगार, विकासशील, असंतुलित, असुलभता, रोजगार, चुनौतियां।*

प्रस्तावना :

आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ने अपनी जड़े कायम कर ली है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार सहित तमाम क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा एक चुनौती की भांति खड़ी है। इस चुनौती का सामना इंसान को धर्म, विवेक व सूझबूझ के साथ करना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई विद्यार्थी अपना विवेक खोकर दबाव व तनाव में आत्महत्या जैसा जघन्य पाप कर रहे है। शिक्षा का उद्देश्य केवल इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना था ना कि किसी के लिए रूकावट का रोड़ा बनकर मानसिक विकृति को जन्म देना। यह सत्य है कि आज की शिक्षा ज्ञान से अधिक रटने पर बल दे रही है। नंबरों की होड़

में विद्यार्थियों को केवल और केवल रटने की कला से परिचित करवाया जा रहा है। कुकुरमुत्तें की भांति हर गांव–गली व मोंहल्ले में खुले स्कूल अपना अस्तित्व बरकरार रखने व प्रवेश प्रक्रिया को तीव्र करने की लालसा में छात्रों को जिला व राज्य स्तर की वरीयता सूची में स्थान दिलवाने के लिए हर हथकंड़ा अपनाते हुए देखे जा सकते है।

आज बच्चों के अंकों व प्रतिशत को ज्यादा तवज्जों दी जा रही है। परीक्षा में अर्जित किए गए नंबरों के आधार पर एक छात्र का सर्वोंगीण विकास व पूर्ण मूल्यांकन किया जा रहा है। अंकों की अंधी होड हमारे देश में हर साल पढ़े–लिखे बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। युवा कर्तव्य विमूढ़ हो रहे है। जरूरत है कि शिक्षा में मूलभूत बदलाव किये जाने चाहिए। स्किल डवलपमेंट के साथ पढ़े–लिखे शिक्षित नागरिकों की बेरोजगारी कम करने के लिए वर्तमान सरकारों को ठोस कदम उठाने चाहिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित **अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन** केवल मोदी सरकार की ही नहीं, इससे पहले की सरकारों की भी इसलिए आलोचना करते रहे हैं क्योंकि उनकी राय में शिक्षा और स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि आर्थिक विकास का आधार मानवीय क्षमता का विकास है। यदि मानवीय क्षमता में वृद्धि नहीं होगी और कौशलयुक्त श्रम शक्ति उपलब्ध नहीं होगी तो आर्थिक विकास स्थायी रूप नहीं ले सकता। **प्रो. असर्त्य सेन** का यह भी कहना है कि रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना और लोगों को रोजगार के लिए सक्षम बनाना किसी भी सरकार का प्रमुख दायित्व है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इसलिए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केन्द्रित नहीं है। यही नहीं अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले कक्षा चार के छात्र पहली कक्षा का पाठ्यक्रम भी ठीक से नहीं जानते। ऐसे में पूरी शिक्षा प्रणाली की प्रमाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है और वह केवल औपचारिक खानापूर्ति बनकर रह जाती है। कुछ एक आई.आई.टी. या आई.आई.एम. खोल देने से समुचे देश की शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं उठता। उसके लिए बिल्कुल निचले स्तर से उसे ऊपर उठाने का प्रयास किये जाने की जरूरत है ताकि हर स्तर पर सुधार हो सकें।

मानव जीवन की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना वह जीवित नहीं रह सकता है। उन्हीं आवश्यकताओं में से एक है **'शिक्षा'**। शिक्षा हर राष्ट्र के लिए विकास और सशक्तिकरण का आधार है। शिक्षा आज की दुनिया की दैनिक गतिविधियों को समझने और इसमें भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी शिक्षा के द्वारा ही समाज में प्रेम का सन्देश, मानवता का सन्देश फैलाया जा सकता है। रोजगार प्रायः ऐसे कार्यो को कहते हैं जिससे जीविकोपार्जन होता है। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबन्धक, वकील, श्रमिक, कलाकार, आदि कुछ रोजगार के उदाहरण हैं।

सामान्य रूप से कहा और माना जा सकता है और माना भी जाता है कि शिक्षा और रोजगार का आपस में कोई संबंध नहीं है। शिक्षा का मूल प्रयोजन और उद्देश्य व्यक्ति की सोई शक्तियां जगाकर उसे सभी प्रकार से योग्य और समझदार बनाना है। रोजगार की गारंटी देना शिक्षा का काम या उद्देश्य वास्तव में कभी नहीं रहा, यद्पि आरंभ से ही व्यक्ति अपनी अच्छी शिक्षा–दीक्षा के बल पर अच्छे–अच्छे रोजगार भी पाता आ रहा है। परंतु आज पढ़ने–लिखने या शिक्षा पाने का अर्थ ही यह लगाया जाने लगा है कि ऐसा करके व्यक्ती रोजी–रोटी कमाने के योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में आज शिक्षा का सीधा संबंध तो रोजगार के साथ जुड़ गया है, पर

शिक्षा को अभी तक रोजगारोन्मुख नहीं बनाया जा सका। स्कूलों–कॉलेजों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, वह व्यक्ति को कुछ विषयों के नामादि स्मरण कराने या साक्षर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। तात्पर्य यह है कि आमतौर पर स्कूल–कॉलेजों की वर्तमान शिक्षा रोजगार पाने में विशेष सहायक नहीं होती। या फिर सबके लिए तो सहायक नहीं हो पाती, अतः उसे रोजगारोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। आज सभी समझदार लोग इस तथ्य को पूर्ण शिद्दत के साथ महसूस करने लगे हैं।

स्कूल, कालेजों में कुछ विषय रोजगारोन्मुख पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स, साइंस के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि के क्षेत्रों में अपनी शिक्षा को नया रूप देकर रोजगार के पर्याप्त अवसर पा जाते हैं। आज कई तरह से भी तकनीकी–शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसे विस्तार भी दिया जा रहा है। पॉलिटेकनिक, आई.टी. आई. जैसी संस्थाएं इस दिशा में विशेष सक्रिय हैं। इनमें विभिन्न ट्रेड्स या कामधंधो, दस्तकारियों से संबंधित तकनीकी शिक्षा दी जाती है। उसे प्राप्त कर व्यक्ति स्व–रोजगार योजना भी चला सकता है और विभिन्न प्रतिष्ठानों में अच्छे रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकता है।

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को एक सुनागरिक बनाने के साथ ही साथ समान रूप से जीवनयापन के लिए तैयार करना भी है। इस दृष्टि से श्रम और अवबोध के साथ–साथ कौशलयुक्त क्रिया सम्पादन भी शिक्षा का ज्ञान एक अविभाज्य अंग हो जाता है। वास्तव में अर्जित ज्ञान का निजी जीवन में उपयोग करना ही वास्तविक शिक्षा है। व्यवसायिक शिक्षा ने शिक्षा में अपना एक अलग स्थान बनाकर शिक्षा के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। वर्तमान समय में व्यवसायिक शिक्षा राष्ट्र की आवश्यकता बन गई है ताकि विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी को कुछ व्यवसायिक गतिविधि में डालकर रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इसी लक्ष्य को देखते हुए समय समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों ने भी विद्यार्थी शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने की बात कही है। व्यसायोन्मुख शिक्षा आज की परिस्थितियों में सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है। वह शिक्षा पद्धति जो व्यक्ति को रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से निर्माण न कर सके, श्रम के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण उत्पन्न न कर सके, केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही प्रदान करती हो, व्यर्थ ही सिद्ध होगी। आज कल बी.ए., एम.ए., पास व्यक्तियों की बेरोगारी की समस्या बनी हुई है। माध्यमिक स्तर तक सभी विषयों की जारकारी दी जा सकती है। किन्तु सीनियर, माध्यमिक स्तर पर व्यसायोन्मुख शिक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित आध्यापकों की कमी, तकनीकी सामाग्री, प्रयोगशालाओं एवं भवन की अपर्याप्तता के कारण व्यवसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में व्यवसायीकरण की व्यवस्था की गई है। यह निश्चय किया गया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सन् 2024 तक 10 प्रतिशत तथा सन् 2026 तक 20 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायें ताकि छात्र रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली में निम्नलिखित समाजोपयोगी उत्पादन कार्यो का कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। कक्षा 6 से 8 तक मुद्रण, प्लास्टिक कार्य, रद्दी कागज की लुगदी, चिकनी मिट्टी से बर्तन, मॉडल बनाना, झालर बनाने का कार्य, बागवानी, लकड़ी का कार्य, कम्प्यूटर, खिलौने बनाना, सिलाई, कढ़ाई–बुनाई, आदि से सम्बन्धित कार्य अनुभव प्रदान कराया जा रहा है। उपयुक्त कार्यक्रम से स्पष्ट है कि छात्र कक्षा 6 की शिक्षा के दौरान ही कोई भी व्यवसायिक कोर्स चुन सकता है ताकि भविष्य में वह शिक्षा के

साथ–साथ रोजगार का जरिया भी अपने लिए मजबूत कर ले। इस प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की भीड़ कम हो सकती है, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के प्रति छात्रों में जागृति उत्पन्न हो जाती है और वे बाद में पॉलीटेकनिक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि में पूर्णकालिक ट्रेनिंग प्राप्त कर किसी व्यवसाय के लिए उपयुक्त बन सकते है।

नई शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत शिक्षा के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनेक उपाय सुझाव गए हैं– वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के छात्रों को कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के उपरोक्त इंजीनियरी एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु 100 व्यवसायिक संस्थाएं स्थापित की जाये। व्यवसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद, उच्च माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकों की संख्या के 70 प्रतिशत को वजीफा प्रदान करेगी। राज्यों के व्यवसायिक शिक्षा के विभागों के सहयोग से **''शिक्षार्थन प्रशिक्षण प्रादेशिक परिषदों''** के द्वारा छात्रवृत्ति देने वाली योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। व्यवसायिक विषयों में डिप्लोमा और डिग्री से सम्बन्धित कार्यक्रम पॉलिटेकनिक, संबंद्ध विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चालू किए जाएंगे। राज्य शैक्षणिक परिषदों एन.सी.ई.आर.टी. तथा अन्य शैक्षणिक परिषदों के माध्यम से आध्यापकों एवं प्रधानाचार्यो को भी व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्त्रियों, आदिवासियों और दूसरे कमजोर वर्गो के लिए आवश्यकतानुसार विशिष्ट व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य विभागों के अन्तर्गत करके इन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाये। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने के लिए जिला स्तर पर जिला व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी परन्तु अभी इस सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। कक्षा 12 के बाद शिक्षा प्रणाली में प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करके शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाना अति आवश्यक है ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन योग्य बन सके। निम्न तथा मध्यम स्तर के टेक्नीशियनों की कमी को वे छात्र पूरा कर सकेंगे जिनकी अध्ययन में विशेष रूचि नहीं होती है। मशीनों को फिट करने, बिजली के समान की मरम्मत, बिजली की मरम्मत, मोटर के हिस्सों की मरम्मत, इंजन ठीक करने आदि से सम्बन्धित व्यवसायिक शिक्षा देने की आज के युग में विशेष आवश्यकता बन गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि तकनीकी शिक्षा का पाठ्यक्रम न केवल विशिष्ट व्यवसायों में विशेषज्ञता प्रदान करने वाला हो बल्कि अर्द्धकुशल कारीगरों को प्रशिक्षण देने वाला अधिक हो, जिससे कम अवधि में कम कुशल छात्र साधारण प्रकार के छोटे–छोटे कार्यो को सीख सकें। अच्छा हो यदि तकनीकी शिक्षा के ज्ञान को भी भारतीय भाषाओं के साथ पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये, जिसे छात्र आसानी से समझ सके।

वास्तव में हस्तकौशल को बढ़ावा देकर बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। शिक्षा के साथ–साथ रोजगार की शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराना या उन्हें रोजगार के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होनी चाहिए। रोजगारन्मुखी बन रही शिक्षा में उच्चत्तर और पेशेवर शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसमें चुनौतियां भी बहुत है। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों पर निगरानी और उनके पाठयक्रम को बेहतर करने पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी ओर बड़ी आबादी और बढ़ते श्रम को पिछले कुछ वर्षों से रोजगार उपलब्ध करा पाना सरकार के लिए बड़ी समस्या सिद्ध हो रही है। **प्रो. अमर्त्य सेन** ने एक साक्षात्कार के दौरान यह कहा था कि

भारत एक मात्र ऐसा देश है जो अशिक्षित और स्वास्थ रहित कार्यबल के आधार पर वैशविक आर्थिक शक्ती बनने का प्रयास कर रहा है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। **प्रौ. अमर्त्य सेन** के विचारों के अनुसार कभी ऐसा होगा भी नहीं।

सर्वोत्तम शिक्षा और आर्थिक बढ़ोत्तरी में एक निश्चित संबंध है। गुणवत्ता वाली शिक्षा से कार्यबल में गुणवत्ता आती है तथा इसके कारण उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती है यही कारण है कि अधिकतर यूरोपीय राष्ट्रों ने सार्वभौमिक शिक्षा को अपना लिया है, जिसे बाद में अमेरिका और जापान ने भी अपना लिया है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, होंग–कोंग, सिंगापुर तथा चाइना में भी यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया और गुणवत्ता वाले रोजगार को कार्यबल की गुणवत्ता से अलग करने का विचार एक गम्भीर आर्थिक समस्या है। बाजार अर्थव्यवस्था के पिता कहे जाने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम् स्मिथ ने 1776 में ऐसी समझ के विपरीत जागरूक कर दिया था। उनकी समझ सही थी की भारत में अंग्रेजी सरकार बेसिक शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आजादी के बाद की लगभग सभी सरकारों ने भी यही गलतियाँ की है। मौजूदा सरकार भी यही कार्य कर रही है। देश के कथित **''डेमोग्राफिक डिविडेंन्ड़''** यानी बड़ी युवा जनसंख्या से बड़ी उम्मीदों के अनुरूप तत्कालीन सरकार का कार्यकाल प्रारम्भ हुआ था। अभी भारत की आबादी का 64 प्रतिशत से ज्यादा भाग 15 से 59 साल की उम्र के कामकाजी दायरे में है। इतना ही नहीं 27 प्रतिशत जनसंख्या 14 वर्ष उम्र तक की है और 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की जनसंख्या तकरीबन 8 प्रतिशत से कुछ ज्यादा है।

इस प्रकार की जनसंख्या को भिन्न–भिन्न प्रकार के रोजगारों की जरूरत होती है। यह हालात अगले 25 सालों तक ज्यों के त्यों बने रहेंगे। इसे बहुत से अर्थशास्त्री और आर्थिक जानकार एक अच्छी स्थिति मानते है। परन्तु इसका एक अन्य पहलू भी है। युवा जनसंख्या एक प्रकार से दो धारी तलवार है। यदि इसे रोजगार के समस्त अवसर उपलब्ध नहीं कराये गये तो युवा बैचेन हो सकता है तथा भविष्य में समाज के ऊपर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। भारत में साक्षरता की वर्तमान दर उपलब्ध जानकारियों के अनुरूप करीब 74 प्रतिशत है। इसमें भी स्त्री–पुरूष और क्षेत्रों के आधार पर बड़ी विभिन्नता है। पुरूषों एवं स्त्रियों की कुल साक्षरता दर क्रमशः 82.14 तथा 65.46 प्रतिशत है वही केरल राज्य में स्त्री–पुरूष साक्षरता दर लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा है। राजस्थान, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्य भी है जहां पर साक्षरता क्रमशः मात्र 67.06, 66.50 तथा 63.82 प्रतिशत है। सभी स्तरों वाले विद्यालयों की संख्या 2014–15 में 15 लाख से कुछ अधिक थी। उस समय तकरीबन 38 हजार कालेज, 760 अलग–अलग प्रकार के विश्वविद्यालय और 12 हजार लगभग तकनीकी शिक्षण संस्थान थे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि साक्षरता की दर तथा शैक्षणिक संस्थाओं में असमानता बेहद दुखदः और चिंताजनक है।

वर्तमान सरकार ने **''स्किल इंडिया''** कार्यक्रम बहुत उत्साह से शुरू किया था लेकिन उसके लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही और नतीजा यह हुआ कि अब संबद्ध मंत्रालय का कहना है कि भविष्य में लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किये जाएंगे और पूरी प्रक्रिया माँग के अनुरूप होगीं। साधारण शब्दों में लोगों को उन्हीं क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें माँग होगी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत रोजगार का रिकार्ड भी बहुत खराब है। वर्ष 2016–17 में लगभग 16.6 प्रतिशत तथा 2017–18 की अवधि में अब तक लगभग 9

प्रतिशत सफल प्रशिक्षु रोजगार प्राप्त कर सके हैं। इस तरह से अभी गुणवत्तापूर्ण श्रम बल तैयार करने तथा बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रक्रिया बहुत दुखद और चिंताजनक नजर आती है। यदि हम ऐतिहासिक रूप से देखे तो वोकेशनल प्रशिक्षण का मॉडल बुरी तरह से असफल साबित हुआ है। कई अन्य कार्यक्रमों की तरह **"स्किल इंडिया"** की चर्चा तो खूब हुई पर आज हालत यह है कि छोटी अवधि के पाठ्यक्रम के मॉडल भी कामयाब नहीं हो पा रहे है। छोटे, मझोले और बड़े उद्योग और उद्यम जरूरत भर रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे है। ऐसे में सेवा क्षेत्र खासकर असंगठित क्षेत्र पर भारी दबाव बढ़ता जा रहा है जहां लोग गुजर–बसर की मजबूरी के कारण जा रहे है।

नये विश्वविद्यालय और कॉलेज नहीं खोले जा रहे है और मौजूदा सरकार के दौर में दक्षिणपंथी ताकते कुछ अच्छे उदारवादी विश्वविद्यालयों का माहौल बिगड़ने पर तुली हुई है। निजी शिक्षण संस्थाएं समाज और आबादी के उन तबकों को सेवा दे रही है जहां से उनहें कमाई और मुनाफें की उम्मीद है तथा यह बात ऐतिहासिक रूप से साबित हो चुकी है कि निजी संस्थाएं कभी भी सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं का विकल्प नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके लिए मुनाफा सबसे अहम लक्ष्य है। इस तरह से आज जरूरी यह है कि अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित हो ताकि सक्षम और निपुण श्रमबल तैयार किया जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि गुणवत्ता के द्वारा और रोजगार के क्षेत्र में मंदी की हालत की प्रक्रिया 2024 में भी जारी रहने की आशंका है। वर्ष 2018 तक बेरोजगारों की जनसंख्या लगभग 1.8 करोड़ तक पहुंच गई हैं, संयुक्त राष्ट्र श्रम रिपोर्ट में इस पर बड़ी चिंता जताई गयी है। इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए केन्द्र सरकार देश की पहली राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने पर विचार कर रही है। वर्ष 2024 के बजट में इस बाबत घोषणा की जा सकती है। यह नीति आर्थिक सामाजिक व श्रम नीतियों के माध्यम से विभिन्न सेक्टरों में गुणवत्ता युक्त नौकरियों के सृजन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी। राष्ट्रीय रोजगार नीति के तहत श्रम प्रधान क्षेत्र के नियोक्ताओं को सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकती है, ताकि अधिकाधिक नौकरियों का सृजन हो और कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराया जा सके। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिल सकें क्योंकि आज भी हमारे देश का लगभग 60 करोड़ श्रमबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, यह वह क्षेत्र है जहां कर्मचारियों के लिए न ही कोई सामाजिक सुरक्षा कानून लागू होता है, न ही उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाता है।

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में युवाओं को रोजगार मुहैया कराना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भारत में जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, वैसे–वैसे खेती से लोग विमुख हो रहे है। बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे है। बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। देश में खेती और इससे जुड़े क्षेत्र सबसे बड़े रोजगार प्रदाता हैं। लेकिन बीते दशकों के दौरान खेती, टैक्सटाइल और लैदर इण्डस्ट्री में रोजगार के मौके घट गये है। हालांकि सर्विस सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों में रोजगार के मौके सृजित हो रहे है। लेकिन इसके लिए व्यापक पूंजी और तकनीक की आवश्यकता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में रोजगार के मौके सीमित है।

भारत ने 2026 तथा उच्च शिक्षा में **ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियों (GER)** का 30 प्रतिशत तक का लक्ष्य रखा है। 18 से 23 वर्ष उम्र समूह की आबादी में उच्च शिक्षा में कुल **एनलोमेंट को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियों (GER)**

कहते है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्ष 2015–16 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियों (GER) 24.5 प्रतिशत था जिसमें वर्ष 2004–05 के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई है। लेकिन यदि हम इस लिहाज से भारत की तुलना चीन और ब्राजील से करेंगे तो चीन में जहां यह 26 प्रतिशत है वही ब्राजील में यह 36 प्रतिशत है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कक्षा 6 के बाद ही उसे व्यवसायों से जोड़ देने की आवश्यकता है। परन्तु आज तक सभी प्रदेशों के विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा में सम्बन्धित साधारण कार्य अनुभव प्रदान करने के अतिरिक्त विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली सामान्यता छात्रों को निश्चित दिशा प्रदान नहीं कर पा रही है। छात्र को सैद्धान्तिक ज्ञान तो मिल जाता है क्योंकि उसका व्यवहारिक प्रयोग वह नहीं जान पाता। किसी विशेष विभाग में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति ट्रेंड कर दिए जाते है और बाद में उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा न होने के कारण अनेक मेधावी छात्र विषय को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उच्च स्तर की पुस्तकें अधिकांश अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में तो वृद्धि हुई है लेकिन गुणवत्ता में गिरावट हुई क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षा को व्यापार बनाने की छूट हमारी सरकारों ने दी है। एक और जहां सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता खराब हुई है। वहीं ऐसे शिक्षण संस्थानों से निकलने वाले लोग रोजगार नहीं खोज पा रहे है। उदारीकरण के बाद जिस स्तर पर रोजगार सृजन होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हुआ है। देश में कुशल श्रमिकों की काफी कमी है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसे कार्यक्रम अभी अपनी छाप नहीं छोड़ पाये हैं। कुशल श्रमिकों के अभाव में जहां तक आधारभूत संरचना तथा विभिन्न कार्यों में गुणवत्ता की कमी होती है वही कौशल के अभाव में बेहतर मजदूरी नहीं मिल पाती।

बार–बार कहा जाता है कि भारत युवा देश है और युवा भाक्ति के मामले में हम विश्व में आगे है। लेकिन युवा शक्ति को शिक्षा व रोजगार देकर ही हम इस बढ़ोत्तरी को बना के रख सकते है। अशिक्षित व बेरोजगार व्यक्ति अपराध की तरफ उन्मुख होता है और महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि होती है। इसलिए पिछड़े राज्यों में अपराध की दर ज्यादा है। यही नहीं इस प्रकार के व्यक्ती में सामान्य नागरिक भाव पैदा नहीं हो पाता है और राज्य के नागरिक कानूनों को या तो वह अशिक्षा की वजह से नहीं मानता या उसके अन्दर का विद्रोह उसे मानने नहीं देता। शिक्षित व रोजगार प्राप्त व्यक्ति समाज व देश की रीढ़ होता है। इसलिए जरूरत नजरिया बदलने की है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को मूलभूत आवश्यकता के रूप में स्थापित किया जाये। रोटी, कपड़ा, मकान की सब्सिड़ी आधारित लालीपॉप से समाज व देश प्रगतिशील कभी नहीं हो सकता। जनतांत्रिक सरकारों को राज्य की शिक्षण संस्थानों व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। उन पर बजट आवंटन बढ़ाना होगा। प्राइवेट संस्थानों द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य को व्यापार बनाने पर रोक लगानी होगी। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा जिसमें उद्योग धन्धों को स्थापित प्रशासन देने के लिए प्रयास करने होंगे। शिक्षित व रोजगार प्राप्त व्यक्ति स्वनिर्भर होगा। वे किसी प्रकार की सब्सिड़ी का मोहताज नहीं होगा। देश के कानूनों का पालन करने वाला होगा, नागरिक भाव रखेगा और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसारित करेगा।

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने **''मेक–इन इण्डिया''** का नारा दिया और दुनियाभर के

उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे भारत में अपने सयंत्र लगाकर यहां अपने उत्पादों का निर्माण करें। ऐसा तभी हो सकता है जब विदेशी निवेशकों और उद्योगपतियों को भारत में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध हो। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा और रोजगार को आपस में जोड़ा जाये और छात्रों के लिए नये–नये कौशल और क्षमताएं पैदा की जाये। यह तभी संभव हो सकता है जब आगामी शिक्षा नीति में आवश्यक बदलाव किया जाए और उस पर अपेक्षित मात्रा में खर्च किया जाये। वरना भारत के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जाएगी जो कि भविष्य में एक विकराल समस्या बन सकती है।

शिक्षा रोजगारपरक हो, यह तो निःसंदेह आवश्यक हैं पर यह काम सरकार ठीक प्रकार से कर सकती है या फिर शिक्षा देने वाले निजी उद्यमी ? सरकारी शिक्षा में बदलते समय और बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को बदलने की अधिक क्षमता होगी या फिर निजी शिक्षा में ? साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का एक जरिया देने में समर्थ इस क्षेत्र के द्वारा बंद रखे जाएं या फिर इसे रोजगार का जरिया बनाकर नये प्रयोग एवं नयी संभावनाओं के मार्ग प्रशस्त किये जाए ? इन प्रश्नों पर आज सरकार द्वारा रटे–रटाये तरीके से अलग हटकर थोड़ा रचनात्मक अंदाज में सोचने की जरूरत है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

1. डॉ. कुमार नरेश, राष्ट्रीय शिक्षा, विक्रय प्रकाशन, कृष्णा नगर, दिल्ली, संस्करण–2001
2. डॉ. नागदा भंवरलाल, शिक्षा जगत में नवीन प्रयोग, अंकुल प्रकाशन, उदयपुर, राजस्थान, संस्करण–2001
3. https://m.dw.com/hi/%eo%a4%b6
4. https://www.patrika.com/workfile/education-should-be-focused-on-knowledge-along-with-employment-1430938/
5. https://evirtualguru.com/hindi-essay-on-shiksha-aur-rojgar
6. https://www.prabhatkhabar.com/news/vishesh-aalekh/story/1107760.html.
7. https:/gshidni.com/category/national-issues/education-job-and-society
8. शर्मा, संजीव – बदलनी चाहिए मूलभूत आवश्यकतायें, प्रगति–पत्रिकाः भारतीय रेल, पूर्वात्तर रेलवे, त्रैमासिक पत्रिका, वर्षः 38, जनवरी–मार्च, 2017